नईदुनिया

संपादकीय

कचरे से किस्मत तक, मध्यप्रदेश ने दिखाया रास्ता

स्वच्छता *अब नारा नहीं, नवाचार है। इंदौर ने मेंटर बनकर देपालपुर को चमकता सितारा बनाया, तो उज्जैन, जबलपुर और देवास ने बताया कि कचरा भी सोना बन सकता है। रीवा, सागर, ग्वालियर और बुधनी ने भी जमीन पर बदलाव की तस्वीर पेश की है। स्वच्छ सर्वेक्षण में नवाचार के माध्यम से बदली यह तस्वीर मध्यप्रदेश की नई कहानी कहती है। कभी स्वच्छता का मतलब सिर्फ झाड़ू लगाना समझा जाता था, लेकिन आज इसका अर्थ नवाचार, रोजगार और शहरों की किस्मत बदलना है। इस बार के सर्वेक्षण ने साबित किया है कि मध्यप्रदेश ने स्वच्छता को सरकारी योजना से निकालकर जन आंदोलन और तकनीक का संगम बना दिया है। इसका पहला उदाहरण है स्वच्छ शहर जोड़ी। मेंटर इंदौर और मेंटी देपालपुर द्वितीय। इंदौर के तकनीकी सहयोग से देपालपुर ने सभी 15 वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण और चार श्रेणियों में कचरा पृथक्करण की व्यवस्था लागू की। इसके दायरे में 3,269 से अधिक घर और 868 व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। नगर परिषद ने करीब 1,250 मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक उपचार कर लगभग 2.21 एकड़ भूमि मुक्त कराई। यह मेंटर और मेंटी की सोच का सफल उदाहरण है, जिसमें बड़ा शहर छोटे शहर को अपना अनुभव और तकनीक साझा करता है। इंदौर ने अपना ज्ञान बांटा और देपालपुर को नई दिशा मिली।*

उज्जैन तीन लाख से दस लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम रहा। यहां सभी वार्डों में चार श्रेणियों में कचरा संग्रहण लागू किया गया। डंप साइटों से लगभग 1.47 लाख मीट्रिक टन कचरे का उपचार कर मुक्त भूमि पर उद्यान विकसित किए गए। मंदिरों में अर्पित फूलों से अगरबत्ती और घाटों पर छोड़े गए कपड़ों से थैले बनाए जा रहे हैं। प्रतिदिन 175 टन क्षमता का बायोगैस संयंत्र और 145 टन क्षमता का कचरा छंटाई संयंत्र स्थापित किया गया है। यह धर्म और पर्यावरण का संगम है। महाकाल के फूल अब कचरा नहीं, सुगंध बन रहे हैं। जबलपुर दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में द्वितीय रहा। नगर निगम ने घर-घर कचरा संग्रहण की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। 491 जीपीएस युक्त वाहनों से प्रतिदिन 550 टन कचरा एकत्र किया जा रहा है। कठौंदा स्थित 11.5 मेगावॉट क्षमता का कचरे से बिजली बनाने वाला संयंत्र पूरी क्षमता से संचालित है। बैकलेन से बेस्टलेन अभियान के तहत 150 से अधिक गलियों का कायाकल्प किया गया। 700 से अधिक सफाई मित्रों ने इस अभियान को गति दी। शहर की 30 से अधिक पिछली गलियों को बच्चों के खेल मैदान और पार्क में बदला गया। सूखे कचरे के प्रसंस्करण केंद्र के माध्यम से कचरा बीनने वाले 50 से अधिक श्रमिकों को स्थायी रोजगार मिला। यह केवल सफाई नहीं, सामाजिक बदलाव भी है। देवास पचास हजार से तीन लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम रहा। लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय सम्मान हासिल कर उसने साबित किया कि छोटा शहर भी बड़ी सोच रख सकता है।

रीवा सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ रिवर टाउन बना। यहां जलाशयों और नदियों की सफाई को सीवेज प्रबंधन से जोड़ा गया। चौबीसों घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष से कचरा वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग की गई और बाजारों में गीले तथा सूखे कचरे के लिए ट्विन बिन व्यवस्था लागू हुई। सागर इसी आबादी वर्ग में तृतीय रहा। ऐतिहासिक झील को बचाने के लिए उसमें गिरने वाले 47 नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा गया। बुंदेली लोककला, दीवारी गायन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया। ग्वालियर को राज्य स्वच्छ शहर पुरस्कार मिला। यहां प्रतिदिन 1,200 टन अपशिष्ट प्रसंस्करण, 350 टन क्षमता के बायो सीएनजी संयंत्र और 100 टन क्षमता के निर्माण एवं विध्वंस मलबा पुनर्चक्रण संयंत्र पर काम चल रहा है। साथ ही 5.50 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक निपटान जारी है। बुधनी बीस हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तृतीय रहा। नगर परिषद ने फीडबैक फाउंडेशन के सहयोग से घर-घर जाकर नागरिकों को कचरा पृथक्करण के लिए प्रेरित किया। स्वच्छता अब झाड़ू और तस्वीरों तक सीमित नहीं है। यह नवाचार, रोजगार, पर्यावरण और संस्कृति से जुड़ा अभियान है। मध्यप्रदेश ने दिखाया है कि कचरा समस्या नहीं, संसाधन है। इंदौर की मेंटरशिप, उज्जैन के फूलों से अगरबत्ती, जबलपुर की कचरे से बिजली, रीवा का नदी संरक्षण और सागर की लोककला, ये सभी अपने आप में अनुकरणीय मॉडल हैं। यह अनुभव पूरे देश के लिए सबक है। स्वच्छता की असली तस्वीर कागज पर नहीं, जमीन पर बनती है और मध्यप्रदेश ने इसे करके दिखाया है।

आजकल

फँसा हुआ पैसा निकलेगा, तभी तो पहिया चलेगा

जीएसटी काउंसिल का समझदारी भरा फैसला, इनवर्टेड ड्यूटी का उल्टा गणित अब होगा सीधा। 90 प्रतिशत रिफंड तुरंत मिलने से उद्योगों को राहत। मशीनों पर दिया गया टैक्स भी लौटेगा, एमएसएमई के लिए संजीवनी। जीएसटी रिफंड के फॉर्मूले में बदलाव से इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में काम करने वाले एमएसएमई निर्माताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक फंसा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अधिक मात्रा में वापस मिल सकेगा। 57वीं जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के अनुरूप इनवर्टेड ड्यूटी वाले मामलों में 90 प्रतिशत रिफंड तत्काल प्रोविजनल रूप से देने का प्रावधान किया गया है।

एक नवंबर 2026 से इनपुट सेवाओं पर दिए गए कर को भी रिफंड में शामिल किया जाएगा। वहीं, एक अप्रैल 2027 से कैपिटल गुड्स यानी मशीनों पर दिए गए जीएसटी का रिफंड भी साठ महीने में मिलेगा। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है कि कच्चे माल पर जीएसटी की दर तैयार माल से अधिक हो। मसलन, कच्चे माल पर 12 प्रतिशत और तैयार माल पर पांच प्रतिशत जीएसटी है तो निर्माता का सात प्रतिशत टैक्स फंस जाता है। पहले मुख्य रूप से कच्चे माल पर दिए गए टैक्स का ही रिफंड मिलता था। अब परिवहन, जॉब वर्क, मरम्मत और अन्य सेवाओं पर दिए गए जीएसटी को भी इसमें शामिल करने से उद्योगों को राहत मिलेगी। कपड़ा, जूता, उर्वरक, मोबाइल असेंबली और साइकिल के पुर्जे बनाने वाले अनेक उद्योग इस समस्या से जूझ रहे हैं। उनका पैसा सरकारी खजाने में अटका रहता है। नकदी की कमी के कारण उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और ब्याज चुकाना पड़ता है। इससे उत्पादन, निवेश और रोजगार प्रभावित होते हैं। मशीनों पर दिए गए जीएसटी का रिफंड भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, साठ महीने की अवधि काफी लंबी है। छोटे उद्योगों को पूंजी की जरूरत आज है, पांच साल बाद नहीं।

अब असली परीक्षा फैसले के क्रियान्वयन की है। रिफंड की प्रक्रिया वास्तव में स्वचालित होनी चाहिए, ताकि पोर्टल की तकनीकी अड़चनों और अधिकारियों की अनावश्यक आपत्तियों में पैसा न फंसे। मशीनों पर टैक्स वापसी की अवधि भी कम की जानी चाहिए। कुल मिलाकर यह स्वागतयोग्य फैसला है। फंसा हुआ पैसा उद्योग का खून है। जब रिफंड मिलेगा तो नकदी बढ़ेगी, निवेश होगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और बाजार में मांग बढ़ेगी। उम्मीद है कि भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन तक के छोटे उद्योगों को इसका लाभ जल्द मिलेगा। जीएसटी तभी सही मायनों में गुड्स एंड सिंपल टैक्स बनेगा, जब उद्योगों का पैसा समय पर लौटेगा।

जेन जी की नई जंग, सड़क पर हाँ, बंकर में ना

सर्वेक्षणों ने खोला राज, युद्ध से क्यों डरती है नई पीढ़ी। चालीस प्रतिशत ने कहा, किसी भी कीमत पर बंदूक नहीं। तुर्किये का जोश, इटली का होश और श्रीलंका का पलायन। दो सौ चार करोड़ की युवा आबादी, जो लड़ना नहीं चाहती। सरकार गिरा देंगे, लेकिन सरहद पर नहीं जाएंगे।



हाल के कुछ वर्षों में जेन जी के आंदोलनों के चलते कई देशों में सत्ता परिवर्तन हुए हैं। दक्षिण एशियाई देश हों या यूरोप, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। मौजूदा समय में फ्रांस, अल्बानिया और इटली जैसे देशों में युवा शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच तीन बड़े सर्वेक्षणों ने दुनिया को चौंका दिया है। सर्वेक्षणों के मुताबिक, जेन जी युद्ध से दूर रहना चाहती है। हथियार उठाने से परहेज करने वाली यही पीढ़ी सड़क पर उतरकर सरकारें हिलाने में पीछे नहीं है। यह एक साथ दो तस्वीरें हैं। एक में युवा टायर जलाकर सड़क रोक रहा है, दूसरी में वही युवा कह रहा है कि मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा। यह सिर्फ विरोध नहीं, नई पीढ़ी का नया घोषणा पत्र है।

ब्रिटिश सोशल एटीट्यूड्स सर्वे ने ब्रिटेन में 16 से 34 साल की उम्र के युवाओं से पूछा कि क्या जरूरत पड़ने पर वे सेना में शामिल होंगे? जवाब ने जनरलों के होश उड़ा दिए। 40 प्रतिशत युवाओं ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी परिस्थिति में हथियार नहीं उठाएंगे। सिर्फ 11 से 22 प्रतिशत युवाओं ने ही जरूरत पड़ने पर सैन्य सेवा को प्राथमिकता देने की बात कही। यानी युवाओं का बड़ा हिस्सा कह रहा है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सर्वेक्षण में अमेरिका के 44 प्रतिशत जेन जी युवाओं ने इजरायल को अमेरिकी सैन्य सहायता देने का विरोध किया। शोधकर्ताओं के अनुसार, जेन जी की युद्ध के प्रति यह अनिच्छा बढ़ती जागरूकता से भी जुड़ी है, जो पुरानी पीढ़ियों से भिन्न है। पुरानी पीढ़ी युद्ध को गौरव समझती थी, नई पीढ़ी युद्ध को प्रत्यक्ष हत्याओं के रूप में देखती है। फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण में नाटो देशों में रहने वाले जेन जी युवाओं से सेना में शामिल होने के बारे में पूछा गया। 45 प्रतिशत युवाओं ने सेना में जाने की इच्छा जताई। तुर्किये के युवा सेना में शामिल होने के लिए अपेक्षाकृत अधिक तैयार दिखे, जबकि इटली में केवल 25 प्रतिशत जेन जी युवाओं ने देश के लिए लड़ने की इच्छा जताई। यानी तुर्किये के युवा आगे हैं और इटली के पीछे। स्पेन में युवा फिर सड़कों पर हैं। बुधवार को देशव्यापी हड़ताल का असर दिखाई दिया। आवास संकट और बढ़ते किराये को लेकर बुलाई गई हड़ताल में कई जगह प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर सड़कें रोकीं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। बार्सिलोना और मैड्रिड में सड़कें जाम कर दी गईं। दो प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल का समर्थन किया। मतलब साफ है, युवा सड़क जाम करेगा, लेकिन सीमा पर जाकर लड़ने को तैयार नहीं है।

श्रीलंका में 53 प्रतिशत जेन जी युवा देश छोड़ना चाहते हैं। 29 प्रतिशत युवाओं ने अपने देश के लिए युद्ध लड़ने से भी इनकार किया। जिस देश ने दशकों तक गृहयुद्ध देखा, वहां के युवा अब कह रहे हैं कि हमें देश ही छोड़ना है, लेकिन लड़ना नहीं है। दुनिया की कुल आबादी लगभग 830 करोड़ है, जिसमें जेन जी की संख्या करीब 204 करोड़ है। यानी कुल आबादी में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी इस पीढ़ी की है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हाथ में तिरंगा लेकर सरकार गिरा रही है, लेकिन हाथ में राइफल लेने को तैयार नहीं है। यह दुनिया की रक्षा नीतियों के लिए सबसे बड़ा अलार्म है।

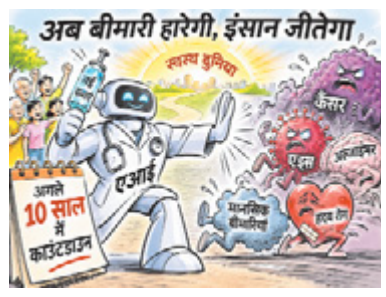
यह पीढ़ी कायर नहीं है, बल्कि उसकी सोच और प्राथमिकताएं अलग हैं। पहला कारण है स्क्रीन। पुरानी पीढ़ी ने युद्ध किताबों में पढ़ा, नई पीढ़ी ने युद्ध रील और वीडियो में देखा है। गाजा के बच्चे हों या यूक्रेन के बंकर, सब कुछ उसकी आंखों के सामने है। इसलिए उसे पता है कि युद्ध में सिर्फ मेडल नहीं मिलते, ताबूत भी मिलते हैं। दूसरा कारण है भरोसे की कमी। यह पीढ़ी नेताओं पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि नेता वातानुकूलित कमरों में बैठकर युद्ध का आदेश देते हैं और गरीब का बेटा अपनी जान गंवाता है। इसलिए वह कहती है कि सड़क पर लड़ेंगे, जहां नेता दिखाई देता है, लेकिन युद्ध के मैदान में नहीं जाएंगे, जहां नेता खुद मौजूद नहीं होता। तीसरा कारण है देशभक्ति की नई परिभाषा। उसके लिए देशभक्ति का मतलब सिर्फ वर्दी पहनना नहीं है। नौकरी, शिक्षा और घर भी देशभक्ति से जुड़े हैं। महंगाई के खिलाफ लड़ना भी देश की सेवा है। यह पीढ़ी फ्रांस में पेंशन के लिए आंदोलन करती है, बांग्लादेश और नेपाल में प्रधानमंत्रियों को सत्ता से बाहर कर देती है, लेकिन जब उससे कहा जाता है कि युद्ध में चलो, तो वही पीढ़ी कहती है कि यह हमारा युद्ध नहीं है। यह पाखंड नहीं, प्राथमिकताओं का अंतर है।

यह पीढ़ी मानती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। बेरोजगारी, महंगाई, आवास संकट और जलवायु परिवर्तन उसके लिए असली युद्ध हैं और वह इन्हीं से लड़ना चाहती है। बंदूक वाला युद्ध तो नेता करवाते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर 40 प्रतिशत युवा हथियार नहीं उठाएंगे तो देश कौन बचाएगा? यदि नाटो देशों में ही आधे से कम युवा सेना में जाने के इच्छुक हैं तो कल की सेना कौन बनाएगा? क्या हम ड्रोन से देश बचाएंगे? क्या हम एआई सैनिक बनाएंगे? यह खतरा भी वास्तविक है। जेन जी का शांतिवाद कहीं मजबूरी तो नहीं? कहीं यह पीढ़ी इतनी थक तो नहीं गई कि उसमें लड़ने की ताकत ही नहीं बची? कोरोना ने बचपन छीना, मंदी ने नौकरी छीनी और जलवायु संकट ने भविष्य की चिंता बढ़ाई। इसलिए अब वह कहती है कि बस, हमें बख्श दो। सड़क पर उतरकर सरकारें हिलाने वाली जेन जी युद्ध के खिलाफ है। यह इतिहास का एक बड़ा मोड़ है। दुनिया बदल रही है। पहले क्रांति बंदूक से आती थी, अब मोबाइल से आ रही है। पहले देशभक्ति का सबूत शहादत था, अब देशभक्ति का सबूत सवाल पूछना है। जो युवा सरकार गिरा सकता है, वह युद्ध के खिलाफ आवाज भी उठा सकता है। उसे डांटने के बजाय समझने की जरूरत है, क्योंकि दो सौ चार करोड़ की यह पीढ़ी अगर युद्ध से दूर जाना चाहती है तो दुनिया को भी युद्ध से दूर जाने के बारे में सोचना पड़ेगा। यही इन सर्वेक्षणों का सबसे आकर्षक और सबसे चिंताजनक सच है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

अब बीमारी हारेगी, इंसान जीतेगा

कैंसर का काउंटडाउन शुरू, दस साल में कहानी खत्म। एड्स का वायरस भी होगा बेघर। दिल और दिमाग की बीमारियों पर भी होगा प्रहार। एआई बना उम्मीद, नई दवाएं बनीं वरदान। इतिहास में दर्ज होगा वह दिन, जब बीमारी हारी। एक समय था जब चेचक और पोलियो का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। फिर विज्ञान आया और इन बीमारियों को इतिहास की किताबों में बंद कर दिया। आज वही कहानी फिर दोहराई जाने की उम्मीद जगी है। कुछ गंभीर बीमारियां, जो आज मौत का दूसरा नाम मानी जाती हैं, उनके इलाज की दिशा में विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है। कैंसर, एड्स, अल्जाइमर, हृदय रोग और मानसिक बीमारियां वे नाम हैं, जो आज भी हर घर में डर पैदा करते हैं। लेकिन अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चिकित्सा अनुसंधान की नई उपलब्धियों ने इनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई की उम्मीद जगाई है।



चैटबॉट बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के प्रमुख ने दावा किया है कि आने वाले एक दशक से भी कम समय में कैंसर, अल्जाइमर, हृदय रोग और मानसिक बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी सफलता मिल सकती है। उनका मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता दवाओं की खोज और चिकित्सा अनुसंधान की गति को कई गुना बढ़ा सकती है। इससे उन बीमारियों का इलाज खोजने में मदद मिलेगी, जिन्हें आज चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में गिना जाता है। इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार भी हैं। एआई की मदद से प्रोटीन संरचनाओं की मैपिंग में बड़ी सफलता मिली है। इससे दवाओं की खोज के नए रास्ते खुले हैं और बीमारियों की जड़ों तक पहुंचना पहले से आसान हुआ है। कैंसर के बारे में सोचिए। आज भी कैंसर का नाम सुनते ही मौत का डर सताने लगता है, लेकिन नई दवाएं और उपचार पद्धतियां इस तस्वीर को बदल रही हैं। ऐसी दवाओं पर काम हो रहा है, जो स्वस्थ कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए कैंसर कोशिकाओं को निशाना बना सकें। पहले कीमोथेरेपी के दौरान बाल झड़ने और शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ने जैसी समस्याएं सामने आती थीं, लेकिन अब लक्षित उपचार के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को चुनकर खत्म करने की दिशा में प्रगति हो रही है। तकनीकी क्षेत्र के कई प्रमुख लोगों का मानना है कि एआई दवाओं की खोज में लगने वाला समय कुछ सप्ताह या महीनों तक सीमित कर सकता है। इससे कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की उम्मीद है। एड्स का वायरस भी जैविक अनुसंधान की सबसे बड़ी चुनौतियों में रहा है। करीब चार दशक पहले जब इस बीमारी का प्रकोप सामने आया, तब इसे लेकर अनेक भ्रांतियां थीं। धीरे-धीरे स्पष्ट हुआ कि यह वायरस से फैलने वाला संक्रमण है। अब नई तकनीकों के माध्यम से वायरस को शरीर से पूरी तरह समाप्त करने की संभावनाओं पर शोध हो रहा है। अभी उपलब्ध दवाएं वायरस को नियंत्रित रखती हैं, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पातीं। एआई की मदद से ऐसे अणुओं की खोज की जा रही है, जो वायरस की प्रतिकृति बनने की प्रक्रिया को रोक सकें। यदि इसमें सफलता मिलती है तो यह मानवता के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हृदय रोग और अल्जाइमर दो ऐसी चुनौतियां हैं, जो चुपचाप जीवन को प्रभावित करती हैं। हृदय रोग में अचानक दिल का दौरा पड़ सकता है, जबकि अल्जाइमर में व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी याददाश्त और पहचान खोने लगता है। बूढ़ा पिता अपने बेटे को भूल जाता है और मां अपने बच्चे को नहीं पहचान पाती। अब एआई की मदद से हृदय की धड़कन और अन्य स्वास्थ्य संकेतों का विश्लेषण कर संभावित खतरे का पहले पता लगाने की दिशा में काम हो रहा है। मस्तिष्क की स्कैनिंग से बीमारी के शुरुआती संकेत पहचानने और नई दवाओं से उसके प्रभाव को कम करने की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। मानसिक बीमारियों के मामले में भी बेहतर पहचान और उपचार की उम्मीद जगी है। इससे उन बीमारियों को लेकर समाज में मौजूद झिझक और कलंक कम करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, इन दावों पर वैज्ञानिक जगत में मतभेद भी हैं। कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों ने इतनी कम अवधि में गंभीर बीमारियों के खात्मे की भविष्यवाणी को अवास्तविक बताया है। उनका कहना है कि दवा बनाना मोबाइल फोन बनाने जैसा नहीं है। किसी भी नई दवा को मनुष्यों पर इस्तेमाल करने से पहले कई चरणों में परीक्षण करना पड़ता है। उसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करनी होती है। इसके बावजूद वे स्वीकार करते हैं कि एआई ने अनुसंधान की गति बढ़ाई है। जो काम पहले दस से बारह साल में होता था, उसे अब पांच से छह साल में पूरा करने की संभावना बन सकती है। वर्टेक्स जैसी बड़ी कंपनियां भी एचआईवी के उपचार के लिए नए विकल्पों पर अनुसंधान कर रही हैं। इसलिए आने वाला दशक चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सोचिए, अगर इन बीमारियों के उपचार में निर्णायक सफलता मिल गई तो दुनिया कैसी होगी। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ कम होगी, परिवार उजड़ने से बचेंगे और असमय होने वाली मौतों में कमी आएगी। बच्चे अपने माता-पिता का साथ लंबे समय तक पा सकेंगे और बुजुर्ग बेहतर जीवन जी सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इंसान बीमारी के डर से मुक्त होकर जीवन जी सकेगा। आज लगभग हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं यह आशंका रहती है कि उसे कैंसर न हो जाए या अचानक दिल का दौरा न पड़ जाए। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति इस डर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इसलिए यह आलेख केवल बीमारियों के खात्मे की कल्पना नहीं, बल्कि उम्मीद के जन्म की कहानी है। विज्ञान ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों पर विजय हासिल की है। अब कैंसर, एड्स, अल्जाइमर और हृदय रोग जैसी चुनौतियों से लड़ाई तेज हो रही है। हालांकि इनके पूरी तरह समाप्त होने की समय-सीमा तय करना अभी संभव नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान ने मानवता के सामने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। आने वाली पीढ़ियां शायद चिकित्सा विज्ञान के इस दौर को एक बड़े बदलाव के रूप में याद करेंगी। वह दिन मानव इतिहास का गौरवशाली दिन होगा, जब बीमारी पर इंसान की जीत का नया अध्याय लिखा जाएगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

सांसद जी का बयान, पसोपेश में किसान

तीन महीने काम, नौ महीने मौज की नई परिभाषा। जो पसीने में भीगता है, वह ताश खेलता है, वाह! चिलम पीने वाला वैज्ञानिक, जिसे अब तक पहचाना नहीं गया। गौशाला में मिला किसान का असली टाइम टेबल।

भोपाल से लेकर रीवा तक किसान इस समय गहरे पशोपेश में है। वह सोच रहा है कि वह किसान है या मौज-मस्ती करने वाला कोई जीव। वजह है भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान। उन्होंने मऊगंज जिले के ग्राम रकरी स्थित गौशाला में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसान केवल तीन महीने मेहनत करके खेती करता है, बाकी नौ महीने ताश खेलता है, तंबाकू-गुटखा खाता है, बोतल से चिलम पीता है और मौज करता है। सांसद के इस बयान से किसानों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। यदि सांसद जी की मानें तो किसान देश का सबसे बड़ा मौज करने वाला प्राणी है और खेती तो बस टाइम पास है।

सांसद जी ने कहा कि किसान तीन महीने काम करता है। वाह! क्या खोज है! देश के कृषि वैज्ञानिक, जो पिछले सत्तर साल से शोध कर रहे हैं, वे तो बेवकूफ निकले। उन्हें आज तक पता ही नहीं चला कि गेहूं सिर्फ तीन महीने में उगता है और बाकी नौ महीने खेत में ताश की दुकान चलती है। किसान बेचारा क्या जाने! वह अप्रैल में गेहूं काटता है तो मई में खेत खाली पड़ा रहता है। जून में हल चलाता है, जुलाई में बीज बोता है, अगस्त में निराई करता है, सितंबर में खाद डालता है, अक्टूबर में फिर जुताई करता है, नवंबर में फिर बोता है, दिसंबर में पानी देता है, जनवरी में कीटों से फसल बचाता है, फरवरी में रखवाली करता है और मार्च में फिर फसल काटता है। यह बारह महीने का चक्कर सांसद जी की नजर में तीन महीने का खेल है। सचमुच, किसान को भी अब पता चला होगा कि वह कितना फालतू समय बर्बाद करता है। किसान ताश खेलता है! अब गांव में जाकर देखिए कि ताश कौन खेलता है। सुबह चार बजे उठकर किसान जब खेत में जाता है तो उसके हाथ में पत्ते नहीं, फावड़ा होता है। दोपहर में जब तापमान 45 डिग्री होता है, तब वह पेड़ की छाया में पांच मिनट सुस्ताता है तो सांसद जी को लगता है कि वह ताश खेल रहा है। अरे साहब, वह ताश नहीं खेल रहा, अपनी कमर सीधी कर रहा है, जो सुबह से झुकी हुई है। वह अपना पसीना पोंछ रहा है, जो आंखों में जा रहा है। लेकिन दूर से देखने पर वह ताश ही लगता है, क्योंकि कुर्सी पर बैठकर देखने की आदत हो गई है। खेत की मिट्टी में पसीना नहीं दिखता, एसी वाले कमरे में ताश ही दिखाई देता है।

किसान चिलम पीता है, बोतल से तंबाकू-गुटखा खाता है। यह तो और भी शोध का विषय है। सांसद जी ने किसान का एक नया रूप खोजा है, एक ऐसा कलाकार जो खेत में चिलम पीते हुए दर्शन देता है। अब सच सुनिए, गांव में चिलम कौन पीता है? वह मजदूर जो दिनभर ईंट ढोता है, वह किसान जो रातभर फसल की रखवाली करता है, ठंड में ठिठुरता है और नींद भगाने के लिए एक-दो कश लगा लेता है। क्या वह अपराधी है? क्या वह नशेड़ी है? नहीं साहब, वह थका-हारा आदमी है, जिसके पास कभी-कभी चाय के लिए भी पैसे नहीं होते और आप उसे चिलमबाज कह रहे हैं। गुटखा खाता है तो क्यों खाता है? क्योंकि वह सुबह से भूखा है, रोटी खाने का समय नहीं है और गुटखे से भूख दब जाती है। यह शान नहीं, मजबूरी है। लेकिन जिसे कभी भूख नहीं लगी, उसे यह मौज लगती है।

सांसद जी का यह बयान कोई नया नहीं है। यह उस सोच का प्रतीक है, जो किसान को हमेशा दोयम दर्जे पर रखती है। जब फसल बर्बाद होती है तो कहा जाता है कि किसान ने मेहनत नहीं की। जब किसान कर्ज मांगता है तो कहा जाता है कि वह शराब में पैसा उड़ा देगा। जब किसान आंदोलन करता है तो कहा जाता है कि वह खालिस्तानी है और जब उसके काम की बात करनी हो तो कहा जाता है कि किसान तीन महीने काम करता है, नौ महीने मौज करता है। वाह रे न्याय! यह वही किसान है, जो आपकी थाली में रोटी रखता है और उसी को आप ताशबाज बता रहे हैं। यह वही किसान है, जिसके बेटे सीमा पर खड़े हैं और उसी को आप गुटखेबाज बता रहे हैं। अब किसान पशोपेश में है कि करे तो क्या करे? यदि वह तीन महीने ही काम करता है तो बाकी नौ महीने क्या करे? सांसद जी ने नया रोजगार सुझा दिया है। ताश खेलो, चिलम पियो और मौज करो। तो क्या सरकार अब मनरेगा में ताश खेलने का जॉब कार्ड बनाएगी? क्या कृषि विभाग चिलम पीने की ट्रेनिंग देगा? क्या गौशाला में अब ताश प्रतियोगिता होगी? सोचिए, कितना अच्छा लगेगा। कृषि मंत्री कहेंगे कि हमने किसानों के लिए ताश योजना शुरू की है। हर पंचायत में ताश क्लब खुलेगा और हर किसान को मुफ्त चिलम दी जाएगी। तब जाकर सांसद जी का सपना पूरा होगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

निलंबित हुए, पर बर्खास्त नहीं, राजनीतिक कवच में आबकारी

जहरीली शराब बिकती है और अधिकारी बच जाता है। मुरैना से देवास तक एक ही पटकथा, एक ही सेटलमेंट। निलंबन रस्म है, सजा नहीं। आबकारी विभाग या वसूली विभाग?

मध्यप्रदेश में अवैध शराब का कारोबार आबकारी विभाग की मिलीभगत के बिना चल ही नहीं सकता, यह सवाल अब लगातार उठ रहा है। भोपाल से लेकर देवास, सागर और हरदा तक जो कुछ सामने आया है, उसने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ताजा उदाहरण जिला आबकारी अधिकारी दीपम रायचुरा का है, जो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी भी रह चुके हैं और वर्तमान में निलंबित हैं। अवैध शराब से जुड़े मामलों में देवास, सागर और हरदा जिलों के कई अधिकारी हाल ही में निलंबित किए गए हैं, लेकिन यह निलंबन रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। जब कोई मामला तूल पकड़ता है तो जनता के गुस्से को शांत करने के लिए अधिकारियों को निलंबित कर मुख्यालय अटैच कर दिया जाता है। जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है, ये अधिकारी राजनीतिक संरक्षण या विभागीय अपीलों के जरिए नौकरी बचा लेते हैं और फिर मलाईदार पदों पर लौट आते हैं।

इस गठजोड़ के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। अगस्त 2026 में मुरैना की कार्यवाहक प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी निधि गुप्ता और शराब ठेकेदार के बीच पैसों के लेनदेन तथा मासिक रिश्वत को लेकर बातचीत का ऑडियो सामने आया था। कलेक्टर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। जुलाई 2026 के अंत में छतरपुर का एक वीडियो बहुप्रसारित हुआ था, जिसमें आबकारी विभाग की सरकारी गाड़ी से शराब की बोतलें



दूसरी निजी गाड़ी में स्थानांतरित की जा रही थीं। देवास जिले में शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना की मौत के मामले में प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित का ऑडियो बहुप्रसारित हुआ था। बातचीत में दो करोड़ रुपये के सेटलमेंट, दबाव और लेनदेन का जिक्र था। धार के तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी संजीव दुबे की भी एक व्हिसलब्लोअर से बातचीत का ऑडियो सामने आया था, जिसमें शराब ठेकेदारों द्वारा राजनेताओं तक लाखों रुपये पहुंचाने और अवैध लेनदेन की बातें सामने आई थीं। उन्हें पद से हटा दिया गया था। सवाल यह है कि पद से हटाना और निलंबित करना क्या सजा है? प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण में आबकारी अधिकारियों और शराब ठेकेदारों के गठजोड़ के कारण लाइसेंसी दुकानों से घटिया शराब की बिक्री और मिलावटखोरी की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। देवास और सागर ही नहीं, इससे पहले मुरैना, मंदसौर, उज्जैन, भिंड और इंदौर में भी जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान जा चुकी है। निगरानी तंत्र की कमजोरी के चलते कुछ आबकारी अधिकारी मन